नितिन गडकरी
Nitin Gadkari

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ
AND DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA

No. W-11012/01/2014-NBA

11th August, 2014

Dear Sir/Madam,

The Ministry of Drinking Water & Sanitation administers the Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) programme with the objective to accelerate sanitation coverage in rural areas to achieve the vision of Nirmal Bharat by 2019. Construction of Individual Household Latrines (IHHL), School and Anganwadi Toilets, Community Sanitary Complexes and Solid Liquid Waste Management are important components of the programme.

2. The status of sanitation in rural areas is not adequate at present as about 60% of our rural population defecate in the open. This leads to health problems in the population and also especially affects women and children in terms of their safety, security and dignity.

3. At present, the following financial assistance under Nirmal Bharat Abhiyan is being provided to States/UTs:

a) **Individual Household Latrines (IHHL):** Rs. 4,600/- (Rs. 5,100/- for hilly and difficult areas). The Central Share out of this is Rs. 3,200/- (Rs.3,700/- for hilly and difficult areas) and State share is Rs. 1,400/- . An amount of up to Rs.5,400/- is also available under MGNREGA. The beneficiary has to contribute Rs.900/-

b) **School Toilets:** Unit cost of School Toilet is Rs. 35,000/- (Rs. 38,500/- in case of hilly and difficult areas). Funding for School Toilets by Central Government and State Government is in the ratio of 70:30.

c) **Anganwadi Toilets**: Unit cost of Toilets in Anganwadis in rural areas is Rs.8,000/- (Rs.10,000/- for hilly and difficult areas). Funding for Anganwadi Toilets is in the ratio of 70:30 by Central Government and State Government respectively.

d) **Community Sanitary Complexes(CSC):** Unit cost for a Community Sanitary Complexes is Rs. 2.00 lakh. Sharing pattern amongst Central Government, State Government and the Community is in the ratio of 60:30:10.

e) **Solid Liquid Waste Management (SLWM):** The total assistance under NBA for SLWM is on the basis of total number of households in each GP, subject to a maximum of Rs. 7 Lakh for a Gram Panchayat having up to 150 households, Rs. 12 Lakh up to 300 households. Rs. 15 lakh up to 500 households and Rs. 20 lakh for GPs having more than 500 households. Funding for SLWM project under NBA is provided by the Central and State Government in the ration of 70:30.

Issued 19/8/14

.....2/

Office: 'G'Wing, Ground Floor, Krishi Bhavan, New Delhi- 110001
Phone: 011-23782373, 23782327, Fax: 011-23385876

4. Requests have been received from various Stakeholders for additional funding for the above activities. It is expected that additional funding will enable the construction of more toilets. There is an urgent need to converge additional financial resources from all sources to this sector. The MPLADS is one of the possible sources of additional support.

5. Extract from MPLADS Guidelines is enclosed for ready reference. MPLADS funds can be provided for construction of IHHLs (without specifying the list of beneficiaries), School and Anganwadi Toilets, Community Sanitary Complexes (Public toilets and bathrooms) and for Solid Liquid Waste Management Activities as the Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) is a Centrally Sponsored Scheme. In such cases, the entire approved unit cost under each scheme (Central and State Share) could be met through MPLAD funds without resorting the convergence with any other scheme.

6. Thus to improve the sanitation facilities in your Constituency, you are requested to recommend the allocation of funds from your MPLADS, for construction of IHHLs (without specifying the list of beneficiaries), School and Anganwadi Toilets, Community Sanitary Complexes (Public toilets and bathrooms) and for Solid Liquid Waste Management Projects to meet full approved unit cost (Centre and State share) in each case under the Scheme. You can, however, specify the geographical areas in which the MPLADS funds are to be spent. This will help to achieve the vision of Nirmal Bharat by 2019 with all Gram Panchayats in the country attaining Nirmal Status and eliminating the scourge of open defecation and squalor in our villages.

With regards,

Yours Sincerely,

(Nitin Gadkari)

Hon'ble Member of Parliament
Rajya Sabha

नितिन गडकरी
Nitin Gadkari

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ AND DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

अ.शा.पत्र **सं.डब्लू- 11012/01/2014 -एनबीए**

अगस्त, 2014

प्रिय महोदय/ महोदया,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, वर्ष 2019 तक निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का संचालन करता है। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल), स्कूली तथा आंगनवाडी शौचालयों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति इस समय संतोषजनक नहीं है क्योंकि लगभग हमारी 60% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। इससे ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा खासकर महिलाओं एवं बच्चों की संरक्षा, सुरक्षा एवं आत्म सम्मान प्रभावित होता है।

3. वर्तमान में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैः-

(क) **वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल):** 4,600/- रुपए (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5,100/- रुपए)। इसमें से केन्द्रीय हिस्सा 3,200/- रुपए (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 3,700/- रुपए) तथा राज्य का हिस्सा 1,400/- रुपए है। मनरेगा के अंतर्गत 5,400/- रुपए तक की राशि भी उपलब्ध है। लाभार्थी को 900/- रुपए का अंशदान देना होता है।

(ख) **स्कूली शौचालयः** स्कूली शौचालय के निर्माण की इकाई लागत 35,000/- रुपए है (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों की स्थिति में 38,500/- रुपए)। स्कूली शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण 70:30 के अनुपात में है।

(ग) **आंगनवाडी शौचालयः** ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाडी में शौचालयों के निर्माण की इकाई लागत 8,000/- रुपए है (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 10,000/- रुपए)। आंगनवाडी शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण 70:30 के अनुपात में है।

(घ) **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी):** सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की इकाई लागत 2.00 लाख रुपए है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा समुदाय के बीच हिस्सेदारी का ढांचा 60:30:10 के अनुपात में है।

(ड.) **ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्लूएम):** एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्लूएम के लिए कुल सहायता, प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर दी जाती है, जिसकी सीमा 150 परिवारों तक की ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 7 लाख रुपए, 300 परिवारों तक की ग्राम पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, 500 परिवारों तक की ग्राम पंचायत के लिए 15 लाख रुपए तथा 500 परिवारों से अधिक तक की ग्राम पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए है। एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्लूएम परियोजना के लिए वित्तपोषण 70:30 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

....2/-

Office: 'G'Wing, Ground Floor, Krishi Bhavan, New Delhi- 110001
Phone: 011-23782373, 23782327, Fax: 011-23385876

4. उपर्युक्त गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण हेतु विभिन्न स्टेकहोल्डरों से अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त वित्त पोषण से और अधिक शौचालयों के निर्माण का मार्ग सुगम हो सकेगा। इस क्षेत्र में सभी स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को इसके साथ जोड़े जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अतिरिक्त सहायता के संभावित स्रोतों में से एक स्रोत एमपीएलएडीएस है।

5. एमपीएलएडीएस के दिशा-निर्देशों का उद्धरण आपके तुरत संदर्भ हेतु संलग्न है। एमपीएलएडीएस निधियां, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) (लाभार्थियों की सूची इंगित किए बिना), स्कूली एवं आंगनवाडी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानगृह) और ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं, चूंकि निर्मल भारत अभियान (एनबीए), केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। ऐसे मामलों में, प्रत्येक स्कीम के तहत कुल अनुमोदित इकाई लागत (केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा) को एमपीएलएडीएस निधियों से, बिना किसी अन्य स्कीम के साथ तालमेल करके, पूरा किया जा सकता है।

6. अतः अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि अपने एमपीएलएडीएस में से निधियों के आबंटन की सिफारिश आईएचएचएल (लाभार्थियों की सूची इंगित किए बिना), स्कूली तथा आंगनवाडी शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए करें ताकि इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में, कुल अनुमोदित इकाई लागत (केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा) को पूरा किया जा सके। तथापि, आप भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण कर सकते हैं, जहाँ एमपीएलएडीएस निधियों को खर्च किया जाना है। इससे देश की सभी ग्राम पंचायतों में 'निर्मल स्थिति' प्राप्त करके तथा खुले में शौच के अभिशाप को दूर करके तथा गाँवों की मलिनता को समाप्त करके वर्ष 2019 तक निर्मल भारत के स्वप्न को सार्थक करने में सहायता मिलेगी।

सादर,

भवदीय

(नितिन गडकरी)

संसद के माननीय सदस्य
राज्य सभा

EXTRACTS FROM MPLADS GUIDELINES

Para 1.3 The objective of the scheme is to enable MPs to recommend works of developmental nature with emphasis on the creation of durable community assets based on the locally felt needs to be taken up in their Constituencies. Right from inception of the Scheme, durable assets of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc. are being created.

Para 3.17 MPLAD Scheme can be converged in individual/stand-alone projects of other Central and State Government schemes provided such works of Central/State Governments Schemes are eligible under MPLADS. Funds from local bodies can similarly also be pooled with MPLADS works. Wherever such pooling is done, funds from other scheme sources should be used first and the MPLADS funds should be released later, so that MPLADS fund results in completion of the project.

Para 3.18 The MPs may recommend augmentation by certain amount out of his MPLADS funds in a Centrally sponsored Scheme against central plus State share indicating the geographical area where to be implemented and the amount recommended, but will not be permitted to indicate the beneficiaries, who will continue to be as per any prior list /priority list already drawn up by the District Authority, and the list would not require a change on the request of the MP.

Annexure II

LIST OF WORKS PROHIBITED UNDER MPLADS

11. Assets for individual/family benefits.(However, as per para 3.28 and 3.28.1 of the guidelines, tri-cycle (including motorised, artificial limbs and battery operated motorized wheelchair to differently abled deserving persons are permitted). **MPs may also provide MPLADS funds to Centrally Sponsored Schemes providing assets for individually family use**, with the proviso that the M.P. will not add or change the priority list or any of the criteria for selection declared in the centrally sponsored scheme. He may not nominate specific individuals as beneficiaries, but can nominate the geographical area where these MPLADS funds would be spent.

Annexure-IVE

LIST OF SECTOR AND SCHEMES CODES

(This is sector wise type of illustrative works under MPLADS and is subject to the provisions in the Guidelines. This is not to be treated as an exhaustive lit, nor a shelf of projects/master list of eligible items under MPLADS).

SECTOR SCHEME

IX. SANITATION AND PUBLIC HEALTH (09)

1. Drains and gutters for public drainage 09001
2. Public toilets and bathrooms 09002
3. Garbage collection and night soil disposal System, earth movers including vehicles for local bodies 09003
4. Other works for sanitation and public health 09999